विचार बिन्दु

वृक्ष अपने काटने वाले को भी छाया देता है। –चैतन्य

यह जो पब्लिक है सब जानती है

गत दो माह से मीडिया में एवं विभिन्न सभाओं में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के चुनाव प्रचार में विभिन्न प्रकार के आश्वासन मतदाताओं को दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वे जनता को बता रहे हैं कि यदि वे सत्ता में आए तो किस प्रकार उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। यह बताने से से भी नहीं चूकते कि अन्य दलों के नेता किस प्रकार के बयान दे रहे हैं एवं किस प्रकार के भाषण दे रहे हैं। प्रत्येक नेता, अन्य दलों के कार्यकाल की, विभिन्न प्रकार के शब्दों से आलोचना करना से नहीं चूकते।

इस पूरे बयान और प्रति – बयान के भ्रम जाल में मतदाता भ्रमित हो रहा है। नेतागण समझते हैं कि जो वे कह रहे हैं, जनता उसको शत प्रतिशत सही मान लेती है। गत कई चुनावों में, इस गलतफहमी को बल मिला भी है। इसी प्रकार जो दल सत्ता में होते हैं, वे उनके द्वारा किए गए कार्यों का इस प्रकार से बखान करते हैं जैसे कोई राम राज्य ही आ गया हो। जनता का अनुभव, कई बार नेताओं के भाषणों के विपरीत होता है। जनता के प्रति नेताओं की यही गलतफहमी कई बार उन्हें ले डूबती है।

आपातकाल के दौरान, जो कुछ भी देश में हुआ, उसके बारे में सत्ता में बैठे नेताओं को कतई जानकारी नहीं थी। वे इसी भ्रम में रहे कि जनता, उनके द्वारा किए गए कार्यों से बेहद खुश है। श्रीमती गांधी ने, इसी भ्रम के चलते, मार्च 1977 में आपातकाल हटाकर चुनाव करवाए और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस की करारी हार हुई और जनता पार्टी सत्ता में आई। इसके बाद, विभिन्न चुनावों में अलग-अलग प्रकार के हथकंडे विभिन्न दलों द्वारा अपनाए गए हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर, विभिन्न प्रकार के स्वप्न जनता को दिखाए गए, जिनसे प्रभावित होकर जनता ने ऐसे लोगों को बहुमत से सत्ता में बिठाया। कहा जाता है कि आप एक व्यक्ति को कई बार मूर्ख बना सकते हैं, कई व्यक्तियों को एक बार बना सकते हैं किन्तु सभी व्यक्तियों को सदैव मूर्ख नहीं बना सकते।

देश के पाँच राज्यों में विधानसभा के चुनाव मे हो रहे हैं। यह जनता पर निर्भर है कि विभिन्न दलों द्वारा किए जाए जा रहे वादों एवं दिए जा रहे आश्वासनों पर जनता विश्वास करती है अथवा नहीं। गत कुछ वर्षों में सोशल मीडिया का प्रचार-प्रसार तेजी से हुआ है। इन चुनावों में, विशेषकर कोरोना के कारण, चुनाव आयोग ने प्रचार के तौर-तरीकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अब तो लगता है, जैसे पूरा चुनाव ही ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लड़ा जा रहा है। आपको वैसे ही वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिस प्रकार के आप देखना चाहते हैं। आप किसी एक विशेष विचारधारा के किसी वीडियो को एक बार डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर जब भी आप यूट्यूब या फेसबुक को खोलेंगे तो आपको स्वत: बहुत सारे वीडियो एवं समाचार उसी प्रकार के मिल जाएंगे। इसी प्रकार कोई अन्य व्यक्ति, विपरीत विचारधारा का वीडियो डाउनलोड करता है तो उसी प्रकार के वीडियो प्राथमिकता से उपलब्ध होती रहेगी।

एक प्रकार से, सूचना और जानकारी का विस्फोट सोशल मीडिया पर हो रहा है। इसमें यह पता करना भी सरल नहीं है कि कौन सा वीडियो वास्तविक है और कौन सा फर्जी? तकनीक की मदद से आजकल फर्जी वीडियो बनाया जाना बहुत सरल हो गया है। इस प्रकार मतदाताओं के सामने दोहरी मुश्किल आ गई है। एक, पता करना मुश्किल है कि उसे प्राप्त व्हाट्सएप या वीडियो असली है या फर्जी। दो, यदि वीडियो असली भी है तो, उसमें किसी नेता द्वारा कही गई बात कितनी गलत है या सही?

जिस राजनीतिक परिपक्वता का परिचय जनता ने कई बार चुनावों में दिया, उसी प्रकार के विवेकपूर्ण निर्णय की, इस बार अत्याधिक आवश्यकता है। उसे यह भी देखना चाहिए कि जो लोग ठीक चुनाव से पूर्व दल बदल कर रहे हैं, वे केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर वैचारिक मतभेद के आधार पर कर रहे हैं।

गत कुछ दिनों में विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा दिये गए बयानों को ही देख लीजिए। "कोरोना का प्रबंध हमारे राज्य में सर्वश्रेष्ठ हुआ", "कोरोना वायरस के कोई कष्ट हमने नागरिकों को नहीं होने दिया", "हमारे राज्य में कोई बेरोजगारी नहीं है", "हमने किसानों की आय को दोगुना कर दिया है", "हमारे राज्य की जीडीपी किसी भी अन्य राज्य से अधिक तीव्रता से बढ़ी है", "हमने अपने राज्य में अपराधियों का पलायन करा दिया है", "महिलाओं को सुरक्षा, सर्वाधिक हमारे राज्य में प्राप्त है", "किसान भाइयों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है", "हम किसान से केवल एक फोन कॉल की दूरी पर हैं", "हमारी सरकार आने पर राज्य के प्रत्येक महिला के खाते में 20000 वार्षिक जमा कराया जाएगा", "सत्ता में आने पर सबको 500 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी", "किसानों को पूरी बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी और वह भी 24 घंटे", "प्रत्येक व्यक्ति को रहने का घर दिया जाएगा", "भ्रष्टाचार को कतई सहन नहीं किया जाएगा', "इस देश की संपदा पर पहला हक मुसलमानों का है"। नेतागण यह समझते हैं कि लोग उनकी इस प्रकार की बातों पर आंख मूँद कर विश्वास कर लेंगे।

जिस प्रकार की घोषणाएं इन चुनावों में की जा रही हैं, लगभग उसी प्रकार की हर चुनाव के पहले होती रही है। जनता को यह तय करना है कि स्वयं के अनुभव के आधार पर, किसकी बात पर विश्वास करें और कितनी नहीं? जनता ने अपने विवेकशील होने का परिचय कई बार देश के विभिन्न चुनाव में दिया है और झूठे आश्वासन देने वाले नेताओं को अच्छा खासा पाठ पढ़ाया है।

दलबदल का एक बहुत बड़ा क्रम भी इन चुनावों में चला है। कई लोग भाजपा से कांग्रेस, काग्रेस से भाजपा, भाजपा से समाजवादी पार्टी, सपा से भाजपा में गए हैं। जो व्यक्ति एक दल में रहते हुए अपने नेतृत्व की तारीफ करते हुए नहीं थकता था वही, अब उसकी आलोचना चुन-चुन कर कर रहा है। कुमार विश्वास जो एक समय अरविंद केजरीवाल के विश्वस्त व्यक्तियों में थे, वही अब केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बता कर अपना वीडियो जारी कर रहे हैं। यह समझना कठिन नहीं है कि पंजाब के चुनाव के ठीक पहले ही वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब अरविंद केजरीवाल द्वारा उन्हें राज्यसभा में भेजना से मना से मना करने का अब वे बदला ले रहे हों। अचानक उन्हें केवल ज्ञान हुआ और एक वीडियो जारी कर दिया।

जो दल एक-दूसरे के विरुद्ध कठोर, आलोचनात्मक बयान दे रहे हैं, उनमें से, चुनाव के बाद सत्ता में आने के लिए,कौन किससे हाथ मिला ले, कुछ नहीं कहा जा सकता है।

इन पांच राज्यों के चुनाव, विशेषकर उत्तरप्रदेश एवं पंजाब के, 2024 के लोक सभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

जिस राजनीतिक परिपक्वता का परिचय जनता ने कई बार चुनावों में दिया, उसी प्रकार के विवेकपूर्ण निर्णय की, इस बार अत्याधिक आवश्यकता है। उसे यह भी देखना चाहिए कि जो लोग ठीक चुनाव से पूर्व दल बदल कर रहे हैं, वे केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर वैचारिक मतभेद के आधार पर कर रहे हैं। एक कहावत है, "सौ सुनार की, एक लुहार की"। पांच वर्ष तक सत्ताधारी लोग जनता के हितों पर अनेक प्रकार से निरंतर प्रहार करते रहते हैं। चुनाव ही वह अवसर जनता को प्रदान कराते हैं कि वह लुहार की तरह ऐसा प्रहार करे कि नेताओं को सदैव के लिए सबक मिल सके।

मतदाता को इन चुनावों में एक बार पुन: 1974 की फिल्म रोटी के इस गीत को सही सिद्ध करना है:–

ये जो पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, सब पहचानती है.......

आइए, हम आशा करें कि सभी राजनीतिक दल, जनता के विवेक और उसकी क्षमता को कम मानकर न चलें और उसी के अनुरूप वह उससे संवाद करें।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

राशिफल बुधवार 23 फरवरी, 2022

पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2078, विशाखा नक्षत्र दिन 2:41 तक, धुव्र योग प्रात: 8:25 तक, बव करण सांय 4:57 तक, चन्द्रमा आज प्रात: 8:56 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-तुला, मंगल-धनु, बुध-मकर, गुरू-कुम्भ, शुक्र-धनु, शनि-मकर, राहु-वृष, केतु-वृश्चिक राशि में।

रवियोग दिन 2:41 तक है। अमृत सिद्धि योग और राजयोग दिन 2:41 से सांय 4:57 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 2:41 से आरम्भ होगा। आज श्री नाथ पाटोत्सव नाथद्वारा, कालाष्टमी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:51 तक, शुभ 11:15 से 12:40 तक, चर 3:30 से 4:55 तक, लाभ 4:55 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:00, सूर्यास्त 6:20

मेष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। व्यावसायिक मामलों में दुविधा बनी रहेगी।

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा।

वृष
परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कन्या
आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुसंदेश प्राप्त होंगे।

मकर
आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। धन खर्च पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है।

मिथुन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

तुला
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। भावनात्मक कारणों से मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

आगामी वित्तीय बजट से राजस्थान को निजी वित्तीय निवेश को आकर्षित करना चाहिए

इसी सप्ताह राजस्थान सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना वित्तीय बजट प्रस्तुत करने वाली है। गहलोत सरकार इस आगामी बजट से काफी कुछ नया करने की कोशिश कर सकती है क्योंकि आधे से अधिक का कार्यकाल सरकार अपना पूर्ण कर चुकी है। गांधीवादी अशोक गहलोत इस बजट से राजस्थान को कुछ नया देने की कोशिश कर सकते हैं।

तस्वीर का दूसरा पक्ष यह भी है कि अगर प्रति व्यक्ति वित्तीय आय के हिसाब से बात की जाए तो राजस्थान का नंबर भारत में 20 राज्यों के बाद आता है। वर्ष 2019-20 तक प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में 111000 थी। वर्तमान समय में तो स्थिति काफी विपरीत है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान समय में बेरोजगारी की द्वितीय सर्वाधिक दर राजस्थान में है। 19 फरवरी तक राजस्थान में बेरोजगारी की दर 18.।9 प्रतिशत दर्ज की गई थी तथा राजस्थान से अधिक बेरोजगारी की दर मात्र हरियाणा में ही थी। वहीं कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में यह 3 प्रतिशत थी। वर्तमान समय में भारत के 11 राज्यों में बेरोजगारी की दर 5 प्रतिशत से कम है।

अगर कोई राज्य सरकार बेरोजगारी को खत्म करने में विफल रह रही है तो इसके पीछे का एक प्रत्यक्ष कारण निजी निवेश को ढंग से आकर्षित ना कर पाना है तो दूसरी तरफ अपने वित्तीय खर्चों का गलत आवंटन भी है।

गहलोत सरकार के इस कार्यकाल के पिछले सभी वित्तीय बजट का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यह पाया जाएगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वित्तीय ऋण लगातार बढ़ रहा है। 2018-19 में वित्तीय ऋण की मात्रा 37847 करोड़ थी तो वहीं पर अगले वित्तीय वर्ष में ये 22 प्रतिशत से बढ़ी थी।

सरकार के राजस्व घाटे की बात की जाए तो पिछले 3 वर्षों में यह लगातार बढ़ा है। जहां 18-19 में ये 3।.07 प्रतिशत था तो अगले वित्तीय वर्ष में ये 3।.64 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 20-21 के संशोधित वित्तीय प्रस्तुतीकरण में इसे 4।.36 प्रतिशत आंका गया था। राजस्व घाटे का कारण सरकार की वित्तीय आय में कमी है। 2020-21 के आकड़े इसे स्पष्ट भी करते हैं। करों के संग्रहण में उत्पादन शुल्क में 9 प्रतिशत की कमी संशोधित वित्तीय प्रस्तुतीकरण में रखी गई थी, वहीं पर राज्य के विक्रय कर वैट में 8 प्रतिशत की कमी थी। अर्थव्यवस्था के वित्तीय घाटे की बात की जाए तो वह भी पिछले 3 वर्षों में लगातार बढ़ा है।

डॉक्टर पीएस वोहरा

पूंजीगत खर्चों की अगर बात की जाए तो पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने इसे 28 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया था तथा चिकित्सा के क्षेत्र पर कुल 1804 करोड़ रुपए का आवंटन किया था जोकि पिछले वित्तीय वर्ष से 4 गुना अधिक था।

दूसरा पक्ष यह भी है कि वर्ष 18-19 में कुल 19638 करोड रुपए विभिन्न पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए रखे गए थे वहीं पर 19-20 के वित्तीय बजट में इसे घटाकर मात्र 14718 करोड़ कर दिया गया था। आज अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसके पीछे का एक मुख्य कारण यह भी है कि अर्थव्यवस्था के पूंजीगत खर्चों में बढ़ोतरी नहीं हुई है जिसके कारण नई संपदा विकसित नहीं की जा सकी है।

राजस्थान अर्थव्यवस्था की वित्तीय बजट में प्रतिवर्ष कुल वित्तीय खर्चों का 80 से 82 प्रतिशत राजस्व व्यय के होते हैं तथा बाकी बचे 18 प्रतिशत के आस-पास पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन होता है। पिछले 3 वित्तीय बजट तुलनात्मक अध्ययन से यह बताते हैं कि राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन व पेंशन की तुलना वित्तीय ऋण के ब्याज के भुगतान का लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2019-20 में यह करीब 2000 करोड रुपए से बड़ा था। निश्चित रूप से यह एक अच्छे आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह भी पाया जा सकता है कि सरकार लगातार ऊर्जा, रूरल डेवलपमेंट, इरीगेशन के अंतर्गत अपने वित्तीय बजट को घटा रही है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का है। कृषि क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र का अंशदान लगभग समान है। आमूलचूल परिवर्तन हेतु अत्यंत आवश्यक है कि सरकार औद्योगिक क्षेत्र को मुख्यधारा में लाए। राजस्थान भारत के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के माध्यम से 13 प्रतिशत का अंशदान देता है। खनिज पदार्थों की उपलब्धता में भी राजस्थान काफी आगे है परंतु अगर औद्योगिक विस्तार की बात की जाए तो सीमेंट, टेक्सटाइल तथा बड़े वाहनों के लिए कलपुर्जे के उद्योगों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों को अधिक विस्तार दीया जाना चाहिए। कच्चे तेल में भी अधिक से अधिक अवसर खोजे जाने चाहिए ताकि आर्थिक संपन्नता को बढ़ाया जा सके। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि के माध्यम से राजस्थान जीडीपी में 23 प्रतिशत का अंशदान देता है इसलिए सरकार को विभिन्न तरह की लागत को नियंत्रित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करके भी इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है।

इसके अलावा सरकार को छोटे शहरों में सर्विस क्षेत्र को आकर्षित करना चाहिए ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले।

इस बजट से यह भी आशा की जानी चाहिए कि सरकार आने वाले दिनों में निजी वित्तीय निवेश को राज्य में अधिक से अधिक आकर्षित करेगी ताकि अर्थव्यवस्था में एक तेजी लाकर राजस्थान को आर्थिक विकास की नई डगर पर देखा जा सके।

डॉक्टर पीएस वोहरा
आर्थिक मामलों के जानकार

नौकर कौन? जनता या अधिकारी-कर्मचारी?

बहुत बार ऐसा होता है कि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जनता के काम करने में ना केवल अपना सौभाग्य समझते हैं, वरन काम को इतनी तन्मयता से करते हैं कि जनता को दृष्टि भ्रम की नौबत आ जाती है। अलबत्ता कई बार तो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस तरह का व्यवहार यदि सभी अधिकारी-कर्मचारी करने लगें तो समस्याओं की फाइल किसी टैबल पर मिले ही नहीं। किंतु, बड़े अफसोस के साथ यह लिखना पड़ रहा है कि चाहे केंद्र के अधिकारी-कर्मचारी हों, या फिर राज्यों के, अधिसंख्य के बारे में जो राय जन-मानस में बन गई है कि काम नहीं करते , वह अनायास नहीं बनी, उसके पीछे लाखों कर्मियों का परिश्रम और कई दशकों अनुभव है, या कहें कि कड़ा अनुभव है।

सरकारी अधिकारी-कर्मचारी मुख्यत: तीन प्रकार के होते हैं। एक: वे लोग जो बिना किसी लाग-लपेट के समय पर काम करके अपनी टैबल हमेशा साफ रखते हैं। दूसरे: जो काम तो करते हैं, लेकिन थोड़ा आलस से, ना-नुकुर करके और जी-हूजुरी कराकर कर ही डालते हैं, उनकी टैबल सामान्यत: मासिक रुप से साफ होती है। तीसरे: वे ही, जो जब तक वजन नहीं, तब तक काम नहीं। अक्सर ये नीचे वाले दोनों ही प्रकार के कर्मी इस लेख की आत्मा हैं। इन्हीं की वजह से लिखना पड़ रहा है कि नौकर कौन? अन्यथा पहले वाले कर्मी के कारण तो इस लेख के लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी।

रामगोपाल जाट

एक विभाग में सैंकड़ों कर्मचारी और कई अधिकारी होते हैं, जो जनता के लिये ही काम करने के लिये रखे जाते हैं। आप कल्पना कीजिये, जो व्यक्ति जनता की सेवा, मतलब लोगों के काम-काज करने के लिये ही नौकरी पर रखा जाता है, उससे मिलने से पहले यदि जनता सो-सो बार सोचने लगे, तो समझो यह व्यवस्था बनी कैसे? जो अधिकारी-कर्मचारी फरियादी की तरफ झांके ही नहीं, और एक से अधिक बार टोक दे तो डपट-झपट करते देर नहीं लगाये, तो पूछो यह व्यवस्था बनाने का जिम्मेदार कौन है?

क्या यह व्यवस्था एक दिन में बन गई? एक साल में बन गई? एक दशक में बन गई? नहीं !इस व्यवस्था को बनाने में हजारों-हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों की अथक नकारात्मक मेहनत लगी है। ऐसे-ऐसे कर्मचारी-अधिकारी इस व्यवस्था को बनाने के जिम्मेदार हैं, जो बरसों तक इस बात की तनख्वाह उठाते रहे कि वे तो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। कल्पना कीजिये, जिसको नौकरी लगते समय केवल एक ही बात दिखती थी, कि उसे सेवानिवृत्त होने तक सरकारी सीट पर बैठकर केवल जनता के काम करने हैं, वही दो-चार बरस बाद इस बात को पूरी तरह से भूल चुका होता है कि वह सरकारी सेवा में रखा ही क्यों गया था?

मेरा एक मित्र था! जब हम पढ़ते थे, तब उसके पिता सरकारी सेवा में थे वह अकसर कहता था कि सरकारी तनख्वाह लेकर भी मेरे पापा इमानदारी से काम नहीं करते, वह कामचोरी करते हैं और हमेशा वेतन के लिये बातें करते हुये पाये जाते हैं। वह कार्यालय में काम के वक्त भी घर के काम निपटाते रहते हैं । हुआ यूं, कि कुछ बरस पहले वह मित्र सरकारी सेवा में शिक्षक बन गया। शुरुआत में शहर से कुछ दूर विद्यालय में सेवा देने के बाद शिक्षा संकुल में डेपुटेशन पर सेवाएं देने लगा। एक दिन मैं रिपोर्टिंग के लिये शिक्षा संकुल गया था, वहीं पर मिल गया। मुझे बोला, चल कैंटीन में चाय पीते हैं। उसके साथ दो अन्य साथी भी थे। चाय बन ही रही थी कि उनकी बातें पूरे सरकारी सबाब पर आ गई । पिता को कोसने वाला भी वही बात उस दिन कर रहा था। मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ कि यह आदमी ऐसे-कैसे इतना बदल सकता है।

रोचक बात यह भी है कि जिस वक्त हम चाय पी रहे थे, उस वक्त ना तो ड्यूटी टाइम खत्म हुआ था और ना ही लंच हो रहा था, फिर भी हम करीब एक घंटे तक उसके वेतन में से 50 रुपये कटने का गुणा-भाग कर रहे थे। है ना कमाल की बात! तब मुझे लगा कि कहीं सरकारी पानी और सरकारी कार्यालयों के वास्तु में ही तो गड़बड़ नहीं है? लेकिन फिर मैं कहूं, यदि ऐसा होता तो जो 5 या 10 प्रतिशत ईमानदार और मेहनती अधिकारी-कर्मचारी हैं, वे भी तो उन्हीं सरकारी कार्यालयों में ही रहते हैं, वहीं का पानी पीते हैं, वहीं लंच भी करते हैं तो अंतत: मुझे इसका जवाब नहीं मिला है कि नौकर कौन? जनता या अधिकारी-कर्मचारी?

–रामगोपाल जाट,
वरिष्ठ पत्रकार

20 साल से बकाया मजदूरी के लिए संघर्ष कर रहे निरंजन ने अन्न जल छोड़ा

अलवर, (निसं)। अलवर की मॉडर्न शूटिंग फैक्ट्री में 18 साल तक सैंपल मैन के तौर पर काम करने वाले निरंजन 20 साल से बकाया मजदूरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अब निरंजन ने अन्न जल छोड दिया है। 2001 में फैक्ट्री बंद हो गई तब से निरंजन अपने बकाया के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

कानूनी लडाई लड़ने और जीतने के बाद भी निरंजन के हाथ पैसा नहीं आया है। अब निरंजन ने अपने घर के गेट पर लिख दिया है 'अन्न जल छोड़ दिया है, मर जाऊं तो मेरा शव मंत्री टीकाराम जूली के कदमों में डाल देना'।

अलवर के शांतिकुंज में रहने वाले निरंजन ने घर के गेट पर यह भी लिखा है कि मेरा शव मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया जाए, ताकि वह मेडिकल स्टूडेंट्स के काम आ सके। अब मुझे उम्मीद नहीं है कि पैसा मिलेगा। निरंजन की बेटी ने कहा कि पिता नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। पूरे परिवार के शरीर को मेडिकल कॉलेज को सौंप देना ही ठीक रहेगा । निरंजन के एक बेटा और एक बेटी है। 2001 में फैक्ट्री से नौकरी छूटने पर निरंजन ठेला लगाकर फल बेचने लगे। लॉकडाउन में वह काम बंद हुआ तो परिवार के भूखों मरने की नौबत आ गई। 2001 में मॉडर्न शूटिंग फैक्ट्री बंद हो गई थी।

निरंजन को 1500 से 2400 रुपए मासिक सैलरी मिलती थी। सैलरी के बकाया भुगतान के लिए निरंजन ने कोर्ट के चक्कर काटे। 2009 में मॉडर्न शूटिंग फैक्ट्री को सत्यतेज कंपनी ने खरीद लिया। फैक्ट्री का सौदा होने के बाद भी मजदूरों को बकाया भुगतान नहीं किया गया। कोर्ट ने फैक्ट्री को मजदूरों के बकाया भुगतान का निर्देश भी दिया लेकिन अमल नहीं किया गया। 2013 में श्रम विभाग ने सत्यतेज से समझौता करने वाले मजदूरों का पैसा दिलाया था, लेकिन निरंजन सिंह के मामले में कोर्ट में केस चल रहा था। निरंजन समेत 5 मजदूरों का पैसा अटका हुआ था। श्रम न्यायालय ने मार्च 2017 में आदेश दिए। निरंजन को 5 लाख के भुगतान का आदेश जारी हो गया।

■ 'अन्न जल छोड़ दिया है, मर जाऊं तो मेरा शव मंत्री टीकाराम जूली के कदमों में डाल देना'

लेकिन तब से निरंजन अलवर से जयपुर के चक्कर काट रहे हैं। इन सबसे परेशान होकर निरंजन अपने परिवार के साथ 18 दिन की भूख हडताल भी कर चुके हैं। इस मामले में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली कह चुके हैं कि निरंजन का भुगतान होना है, वह प्रक्रियाधीन है जहां मदद की जरूरत है वहां की जाएगी। निरंजन का कहना है कि श्रम मंत्री रहे टीकाराम जूली के आश्वासन के बाद भी श्रम विभाग के अधिकारी टालमटोल करते रहे। कोर्ट के आदेश पर भी पैसा देने में आनाकानी की जा रही है।

इस मामले में श्रम विभाग के अधिकारी राकेश का कहना है कि विभाग के स्तर पर काम पेंडिंग नहीं है। विभाग से अवार्ड घोषित हो चुका है। अवार्ड की पालना नहीं करने पर जिला कलेक्टर जयपुर को भी लिख दिया है। ताकि रिकवरी कर पैसा दिया जाए। इसके बाद जयपुर से रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया में ही समय लग रहा है।

सिलीसेढ के पास गंदगी को देखकर पर्यटक निराश

अलवर, (निसं)। अलवर शहर में प्रसिद्ध सिलीसेढ झील पर गंदगी का आलम बना हुआ है। सिलीसेढ झील अलवर का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। आज जब मीडिया कर्मी द्वारा पर्यटकों से संपर्क किया गया तो उन्होंने झील के पानी में व आस-पास की गंदगी को देखकर निराशा जताई तथा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी क्षेत्र की पर्यटन स्थल को स्वच्छ रखना उस क्षेत्र के प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी होती है लेकिन यहां की गंदगी को देखकर ऐसा नहीं लगता।

सभ्य संक्रमण

अब हम पहले से अधिक सभ्य हो गये हैं। महिला स्वास्थ्य के प्रति चेतना तो चरम पर है। प्रजनन स्वास्थ्य - जनसंख्या विस्फोट के कारण जागरूक राष्ट्र और सभ्य समाज का केन्द्र बिन्दु है । जागरूकता का प्रतीक है देश में प्रति वर्ष 60 लाख से अधिक होते गर्भपात। सभ्य समाज की अनपढ महिलाऐं गर्भपात को सफाई, थोड़ी पढी हुई अबोर्शन या डी एन्ड सी और अगर सुशिक्षित आधुनिक महिला है तो बतायेंगी एम टी पी करवाई थी। 'आबादी की महामारी' के परिप्रेक्ष्य में बने गर्भपात कानून से योगदान देने को सब अपना कर्तव्य मानते हैं। यही कारण है कि कानून के सुरक्षात्मक प्रावधानों की अवहेलना में होते 40 लाख अवैध गर्भपात और उससे होती हजारों महिलाओं की मृत्यु के प्रति सर्वथा अवज्ञा। वैसे कुछ सिरफिरे जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भपात को बर्बरता की संज्ञा देते हैं। कहते हैं कि यह वहशियों का नया धर्म है। अबोर्सन फार पॉपुलेशन कंट्राल इज न्यू रिलिजन ऑफ बार्बेनियन्स अवैध संक्रमित गर्भपात से होने वाली भयानक मृत्यु को देखते हुए तो यह सही लगता है। 40 लाख अवैध गर्भपात के प्रति आंखे बंद रखना, कान बंद रखना, मुंह बंद रखना संवेदनहीनता की पराकाष्टा है, बर्बर हिंसा है।

25 वर्षीय महिला को शहर के जाने माने प्रतिष्ठित उच्च स्तरीय अस्पताल में लाया गया है। हालत गंभीर है। शहर से 120 किलो मीटर दूर कस्बे से लाया गया है जहां, मरीज के कथनानुसार, 3 दिन पहले अबोर्सन करवाया था। पेट फूला हुआ है। भयंकर दर्द है। पेट को दबा कर छोड़ते ही मरीज पीड़ा से कराह उठती है। बुखार है। रक्तचाप गिरा हुआ है। नाड़ी की गति काफी तेज है। चेहरा जर्द है, सांस उखड़ी हुई है। आंतों ने काम करना बंद कर दिया है, उल्टियां हो रही हैं। 24 घंटे से पेशाब नहीं हुआ है, गुर्दे फेल हो रहे हैं। साफ है गर्भपात के दौरान गर्भाशय में छेद हुआ और उससे घुसे औजार से आंत फटी।

ंदर गंभीर मलीय संक्रमण हुआ। पूरे शरीर में तीव्र गति से संक्रमण का जहर फैल गया है। महिला सन्निपात में है। आई सी यू में भरती कर इलाज चालू किया गया। दर्जनों टेस्ट हुए । उंची एन्टीबायोटिक्स दी गई। गिरे रक्तचाप के लिए दवायें और तरल दिए गये। संक्रमण, हृदय रोग और गुर्दा रोग विशेषज्ञों को दिखाया गया। डायालिसिस की गई। लेकिन हालत नही संभली। वेन्टीलेटर पर भी रखा गया मृत्यु हो गई। मुत्यु के प्रमाण पत्र में कारण लिखा गया पेरिटोनियम का गंभीर संक्रमण, रक्त संक्रमण से मल्टी ऑर्गन फेलियोर। उसी अस्पताल का दूसरा केस। 30 वर्ष की विवाहित महिला। वैसे ही 'सफाई' के बाद गर्भाशय और आंत के फटने से पेरिटोनियम का मलीय संक्रमण। वैसी ही दर्दनाक गंभीर स्थिति। फर्क इतना कि इस में सर्जन ने आपरेशन कर पेट खोला, बदबू भरी मवाद को निकाला, धो कर साफ किया और आंत का छेद बंद किया। लेकिन मरीज आपरेशन थियेटर से आई सी यू में अचेत वेन्टीलेटर पर ही लौटी, जहां सघन उपचार के बावजूद उसने दम तोड़ दिया। मृत्यु प्रमाण पत्र में लिखा गया 'सेप्टिक पेरीटोनाइटिस, सेप्टिक शॉक, मल्टीऑर्गन फेलियोर।'

डॉ. श्रीगोपाल काबरा

ऐसे केसेज आम हैं। उच्चस्तरीय अस्पताल स्वाभाविक मृत्यु का प्रमाण पत्र देते हैं और महिला की अंतेष्ठि कर दी जाती है। रिपोर्टस के अनुसार देश में प्रति वर्ष लगभग 10000 महिलाओं की मृत्यु अवैध संक्रमित गर्भपात से होती है। गंभीर मारक संक्रमण, भयंकर मृत्यु।

संवेदनहीनता की परकाष्ठा यह है कि इसकी रोकथाम की कोई चेष्ठा नहीं होती, सब मौन रहते है। अवैध गर्भपात केन्द्र, गांवों में ही नहीं, शहरों में भी खूब फल-फूल रहे हैं। इस के प्रति सब मौन क्यों हैं? क्या तड़प-तड़प कर मरती इन महिलाओं की सुध लेने को कभी कोई 'वर्मा' आयोग बिठाया जायेगा?

अवैध गर्भपात संगीन अपराध है। गर्भ हनन से मातृ हत्या। कानून में प्रावधान है कि अगर किसी महिला की विवाह के सात साल में मृत्यु होती है और साक्ष्य है कि उसके शरीर पर कुछ किया गया था तो पुलिस को इत्तला की जानी चाहिए। हर संक्रमित गर्भपात में ये साक्ष्य बहुलता से होते हैं। पुलिस को ऐसी मुत्यु की इत्तला न देना भी अपराध है। फिर क्यों सब चुप रहते है? सभ्य समाज, सरकार और प्रशासन की चुप्पी क्या कांसपिरेसी ऑफ साइलेन्स - मौन स्वीकृति से लिप्तता नहीं है? दुर्भाग्य यह है कि तथाकथित जागरूक महिला संगठन भी इसमें शामिल हैं। अनचाहे गर्भ को वहन न करने के मौलिक अधिकार का यह विकृत रूप भयानक है। सभ्य समाज में यह कैसा संक्रमण है?

डॉ. श्रीगोपाल काबरा
वरिष्ठ चिकित्सक, जयपुर